नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 116
दि. 29.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

घड़ी की सुई थम गई, सियासत की धड़कन रुक गई:

अजित पवार का असमय जाना महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति

(जीएनएस)। राजनीति के गलियारों में शोर बहुत होता है। वहां हर रोज नए नारे गढ़े जाते हैं, नई रणनीतियां बनती हैं और सत्ता की बिसात पर चालें चली जाती हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र की हवाओं में जो खामोशी तैरी है, वह किसी भी नारे, किसी भी भाषण और किसी भी राजनीतिक शोर से कहीं ज्यादा भारी है। यह खामोशी उस वैक्यूम की तरह है, जो किसी विशाल बरगद के पेड़ के अचानक गिर जाने के बाद जंगल में पैदा हो जाता है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार अब नहीं रहे। बुधवार सुबह एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया और इसके साथ ही राज्य की राजनीति की वह घड़ी थम गई, जिसकी सुइयां दशकों से बिना रुके घूमती रही थीं।

अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति की वह 'घड़ी' थे, जो हालात चाहे जैसे भी हों, चलती रहती थी। लोग कहते थे कि वे सत्ता के खेल के माहिर खिलाड़ी थे, लेकिन हकीकत यह थी कि वे उस नदी की तरह थे, जो अपना रास्ता खुद बनाती है, भले ही उसे पहाड़ काटने पड़ें। आज वह नदी अचानक किसी अदृश्य समंदर में विलीन हो गई। पुणे जिले के बारामती में सुबह करीब 8:50 बजे हुआ यह विमान हादसा न सिर्फ एक बड़े नेता की जिंदगी छीन ले गया, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे अध्याय को अचानक विराम दे गया।

जानकारी के अनुसार, अजित पवार पांच फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में पुणे जिले में चार चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे। मुंबई से दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स द्वारा संचालित लीयरजेट 46 विमान ने सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी थी। उड़ानों की निगरानी करने वाली फ्लाइट रडार के मुताबिक, सुबह करीब 8:45 बजे विमान का रडार से संपर्क टूट गया। बारामती एयरपोर्ट के आसपास उस वक्त घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे दृश्यता बेहद कम थी। बताया गया कि पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे साफ दिखाई न देने के कारण विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाया गया। इसके बाद रनवे-11 पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में विमान धू-धू कर जल उठा।

इस भीषण हादसे में अजित पवार के साथ उनके पीएसओ हेड कांस्टेबल विदिप जाधव, मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर, सहायक पायलट कैप्टन सांभवी पाठक और विमान की क्रू सदस्य पिंकी माली की भी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुर्घटना के बाद विमान में जोरदार विस्फोट हुआ और उसके बाद चार से पांच छोटे-बड़े धमाके लगातार सुनाई दिए। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उतरते समय विमान हवा में अस्थिर नजर आ रहा था। हादसे के तुरंत बाद दमकल विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।

विमान हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की टीमें मौके पर पहुंचीं। जांच एजेंसियों की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी वीएसआर वेंचर्स के दफ्तर भी पहुंची है। कंपनी का दावा है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और पायलट बेहद अनुभवी थे। मुख्य पायलट के पास करीब 16 हजार घंटे का फ्लाइंग अनुभव था, जबकि को-पायलट के पास लगभग 1500 घंटे का अनुभव था। इसके बावजूद हादसा कैसे हुआ, यह जांच का विषय बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि हादसे से पहले कोई 'मेडे कॉल' नहीं दी गई थी। हालांकि, बताया जा रहा है कि सहायक पायलट कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द थे— "ओह शिट ओह शिट"

अजित पवार के निधन की खबर फैलते ही पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। सरकार ने उनके सम्मान में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, जो 28 जनवरी से 30 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। बुधवार को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रखे गए। पुणे से लेकर मुंबई और बारामती तक, हर जगह लोगों की आंखें नम हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है—क्या सच में अजित पवार अब नहीं रहे? अजित पवार का राजनीतिक सफर अपने आप में एक मिसाल रहा है। वे छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे और यह रिकॉर्ड अपने आप में उनकी राजनीतिक ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा के नेतृत्व वाली अलग-अलग सरकारों में उपमुख्यमंत्री के रूप में काम किया। नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ बनी सरकार हो या जुलाई 2023 में भाजपा-शिवसेना गठबंधन में शामिल होना—अजित पवार हर बार राजनीति के केंद्र में रहे। वे एक ऐसे नेता थे, जो फैसले लेने में देर नहीं करते थे और अपने स्पष्ट बयानों के लिए जाने जाते थे। उनके निधन पर देशभर के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अजित पवार एक जननेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था और वे हमेशा महाराष्ट्र की जनता की सेवा में समर्पित रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ी क्षति बताया। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने न सिर्फ शोक जताया, बल्कि इस हादसे की गहन जांच की मांग भी की है।

दिल्ली विधानसभा ने विपक्षी नेता आतिशी को विशेषाधिकार समिति के नोटिस में 6 फरवरी तक लिखित जवाब देने को कहा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को विपक्ष की नेता आतिशी को विशेषाधिकार समिति के नोटिस के माध्यम से 6 फरवरी तक लिखित जवाब देने के लिए कहा है। यह कार्रवाई उन बयानों के संबंध में की गई है जो आतिशी ने शीतकालीन सत्र के दौरान AAP विधायकों के निलंबन को लेकर दिए थे। कथित रूप से उनके बयानों में न केवल तथ्यों के विरुद्ध आरोप लगाए गए, बल्कि सदन की कार्यवाही और गरिमा को प्रभावित करने की कोशिश भी हुई। विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया कि आतिशी को विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपने लिखित जवाब में पूरी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जानकारी के अनुसार, यह मामला उस समय उठाया गया जब आतिशी ने दावा किया था कि चार AAP विधायकों — संजीव झा, सोम दत्त, कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह — को मास्क पहनने के कारण सस्पेंड किया गया था। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि विधायकों को सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के कारण ही सस्पेंड किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतिशी का कथन न केवल गलत था, बल्कि इससे सदन और जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया।

सत्र के दौरान उठे विवाद की पृष्ठभूमि यह है कि 6 जनवरी को शीतकालीन सत्र में उपराज्यपाल के भाषण के दौरान चार AAP विधायकों ने कथित रूप से व्यवधान डाला था। इसके बाद उन्हें सदन की बाकी बैठकों से भी निलंबित कर दिया गया। यह कदम विधानसभा की सुव्यवस्था और गरिमा बनाए रखने के लिए उठाया गया था। स्पीकर ने कहा कि सदन की मर्यादा और कार्यवाही की निष्पक्षता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है, और इस तरह के गलत बयानों को सहन नहीं किया जाएगा।

विशेषाधिकार समिति के नोटिस में उल्लेख है कि आतिशी को मामले में पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण सहित लिखित जवाब 6 फरवरी तक सचिवालय में जमा करना अनिवार्य है। समिति इसके बाद मामले की विस्तृत सुनवाई करेगी और यदि आवश्यक हुआ, तो नियमों और विधान के अनुसार कार्रवाई करेगी। यह प्रक्रिया केवल तथ्य उजागर करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले आरोपों का निराकरण करने के उद्देश्य से की जा रही है।

राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर अब गहन चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे सदन में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास मानते हुए आलोचना की है, जबकि सरकार और विधानसभा के अधिकारी इसे केवल नियमों और विधान के अनुसार उठाया गया औपचारिक कदम बता रहे हैं। यह मामला दिल्ली की राजनीति में आने वाले समय में विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच संभावित टकराव का नया मुद्दा बन सकता है। विपक्ष के नेता और राजनीतिक विश्लेषक इस कदम को विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तापमान बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है। आतिशी द्वारा 6 फरवरी तक जवाब न देने या अधूरा जवाब देने की स्थिति में समिति अधिक कठोर कार्रवाई कर सकती है। इससे विधानसभा के अंदर और बाहर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ सकती है, और यह मामला मीडिया और आम जनता के बीच भी गहन चर्चा का विषय बन सकता है।

विशेषाधिकार समिति का यह कदम न केवल सदन की मर्यादा बनाए रखने की दिशा में है, बल्कि यह भविष्य में विधायकों और विपक्षी नेताओं को सतर्क करने का संकेत भी माना जा रहा है। अब सबकी नजरें 6 फरवरी पर टिकी हैं, जब आतिशी अपने लिखित जवाब के जरिए अपने बयान की सफाई देंगी और समिति इस मामले में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

यह मामला दिल्ली विधानसभा में विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बढ़ते तनाव की तस्वीर को भी उजागर करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और अधिक सियासी ज्वार पैदा कर सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बनाकर उठाएगा, जबकि सरकार इसे नियम और विधान के अनुपालन के रूप में देख रही है। ऐसे में 6 फरवरी को आने वाला जवाब न केवल आतिशी के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि दिल्ली विधानसभा में आगामी सत्रों और कार्यवाही की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है।

कोड और क्लाउड में लड़ी जाएगी आने वाली जंग पीएम मोदी का एनसीसी रैली में ऐतिहासिक संदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली छावनी में आयोजित एनसीसी (नेशनल कैडेट कॉर) की वार्षिक रैली को संबोधित करते हुए भविष्य की सुरक्षा और युद्ध की बदलती अवधारणा पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब आने वाला युद्ध केवल सीमाओं, टैंकों और तोपों तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य के युद्ध का मैदान 'कोड और क्लाउड' यानी डिजिटल और साइबर स्पेस होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म ही राष्ट्र की सुरक्षा और शक्ति का मुख्य आधार होंगे। उन्होंने युवा कैडेटों को चेतावनी दी कि केवल पारंपरिक युद्ध की रणनीतियों में महारत हासिल करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि साइबर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और तकनीकी उत्कृष्टता में दक्षता आवश्यक होगी।

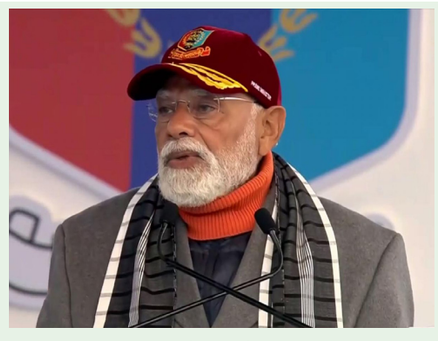

पीएम मोदी ने इस दौरान स्वदेशी हथियार निर्माण और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब न केवल अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए हथियार और उपकरण बनाता है, बल्कि दुनिया के कई देशों को भी इन्हें निर्यात कर रहा है। यह न केवल देश की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि मजबूत रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं से बनती है। एनसीसी कैडेटों की अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यही गुण भविष्य में भारत को सुरक्षित और सशक्त बनाएंगे।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यापार और आर्थिक अवसरों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं। इनमें यूरोपीय संघ, ओमान, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन समझौतों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और लाखों भारतीय युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और उद्यम के अवसर खुलेंगे। उन्होंने युवा वर्ग से अपील की कि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा को अवसर के रूप में देखें और इसे देश की उन्नति और समृद्धि के लिए इस्तेमाल करें।

एनसीसी रैली में प्रधानमंत्री ने 'अमृतकाल' की अवधारणा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी 2047 तक भारत की वैश्विक स्थिति को तय करेगी। युवा अनुशासन, कौशल, नेतृत्व और संस्कार के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिबद्धता और समर्पण ही भारत को विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कैडेटों से आह्वान किया कि वे केवल अपने व्यक्तिगत करियर तक सीमित न रहें, बल्कि देश के निर्माण और सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

प्रधानमंत्री ने डिजिटल और तकनीकी युद्ध की चुनौतियों के अलावा देश की पारंपरिक ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की क्षमता, उनकी प्रशिक्षण प्रणाली और आधुनिक हथियारों से लैस रहना भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने 'कोड और क्लाउड' के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भविष्य के युद्ध में सूचना, डेटा और तकनीकी श्रेष्ठता निर्णायक भूमिका निभाएगी।

कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उनका अनुशासन, उनके कौशल और संस्कार ही देश की ताकत हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाले समय में भारत का सुरक्षित और मजबूत भविष्य उन्हीं के हाथ में है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन ने एनसीसी कैडेटों और देश के युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश छोड़ा कि तकनीकी दक्षता, डिजिटल जागरूकता और देशभक्ति भविष्य के लिए सबसे बड़ा हथियार हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश की सुरक्षा में भागीदारी केवल सेना तक सीमित नहीं है। हर युवा, हर नागरिक और हर तकनीकी विशेषज्ञ का योगदान अब राष्ट्र की मजबूती और सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुका है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और द्रमुक के बीच सीट बंटवारे पर गतिरोध जारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन की चर्चा अभी भी विवादास्पद बनी हुई है। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और द्रमुक (ड्राविड़ियन मुनेत्र कड़गम) की सांसद कनिमोझी के बीच हुई बैठक में भी सीट बंटवारे को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच मतभेद अभी भी स्पष्ट हैं, और राज्य में गठबंधन के रूप और कांग्रेस की भागीदारी को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में मुख्य रूप से उन मुद्दों पर चर्चा की गई जिन्हें जल्द हल करने की आवश्यकता है। हालांकि, बैठक में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई इस बार कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है और राज्य में सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी की मांग कर रही है। इसके विपरीत, द्रमुक कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह गतिरोध गठबंधन में पहले से ही विद्यमान मतभेदों को और बढ़ा सकता है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की संभावित तिथि अप्रैल-मई 2026 बताई जा रही है, और अब समय कम है, ऐसे में सीट बंटवारे पर सहमति बनाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करना दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है।

राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने राज्य में अपनी पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक सीटों की मांग की है। पार्टी का मानना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहीं, द्रमुक का तर्क है कि पार्टी की स्थिति और स्थानीय समीकरणों के हिसाब से कांग्रेस को अधिक सीट देना संभव नहीं है।

विश्लेषकों के अनुसार, यह गतिरोध केवल सीट बंटवारे तक सीमित नहीं रहेगा। यदि जल्द सहमति नहीं बनी, तो गठबंधन में दरार की संभावना बढ़ सकती है। राजनीतिक माहौल पर नजर रखने वाले कई वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व नेता मानते हैं कि कांग्रेस और द्रमुक के बीच संतुलन बनाए रखना अहम है, क्योंकि किसी भी तरह का विवाद गठबंधन की ताकत को कमजोर कर सकता है।

कांग्रेस और द्रमुक के नेताओं के बीच अब कई दौर की बैठकों की संभावना जताई जा रही है। राज्य इकाई के नेताओं का मानना है कि यदि सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी, तो कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों को अकेले मैदान में उतारने पर विचार करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, द्रमुक ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता राज्य में अपने गठबंधन और सीटों की मजबूती है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि तमिलनाडु के इस चुनाव में गठबंधन और सीट बंटवारे का मुद्दा निर्णायक साबित हो सकता है। पिछले चुनावों के अनुभव से यह देखा गया है कि गठबंधन का सही संतुलन और सीटों का न्यायसंगत वितरण राज्य में चुनाव परिणाम को सीधे प्रभावित करता है।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कांग्रेस और द्रमुक के बीच चल रही खींचतान ने अन्य क्षेत्रीय दलों को भी मौका दे दिया है। यदि दोनों पक्ष जल्द से जल्द समाधान नहीं निकालते हैं, तो तीसरे पक्ष को वोट बैंक आकर्षित करने का अवसर मिल सकता है।

राजनीतिक विश्लेषण में यह भी बताया गया है कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल अधिक सीटें हासिल करना नहीं है, बल्कि सत्ता में प्रभावी भूमिका निभाना भी है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व का दबाव रहेगा कि वे अपने उम्मीदवारों और समर्थकों को संतुष्ट रखें। वहीं, द्रमुक की स्थिति राज्य में उसकी ताकत और पिछले चुनावों में मिली सफलता पर आधारित है।

रेलवे में 'गोल्डन विदाई' की परंपरा का अंत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा सोने चढ़ा चांदी का पदक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने अपनी लगभग 20 साल पुरानी 'गोल्डन विदाई' योजना को अचानक समाप्त कर दिया है, जो कर्मचारियों की सेवा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती थी। मार्च 2006 में शुरू की गई इस परंपरा के तहत सेवानिवृत्त होने वाले या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को 20 ग्राम शुद्ध चांदी का पदक दिया जाता था, जिस पर सोने की परत चढ़ी होती थी। यह पदक वर्षों तक रेलवे कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि उनकी मेहनत, निष्ठा और सेवा का प्रतीक माना गया।

रेल मंत्रालय ने हाल ही में जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया कि अब से यह परंपरा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जो पदक स्टॉक में बचे हैं, उन्हें नष्ट करने के बजाय रेलवे के अन्य आधिकारिक पुरस्कारों या गतिविधियों में उपयोग किया जाएगा। इस फैसले को रेलवे के वित्तीय और प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि अब समय बदल गया है और कर्मचारियों को सम्मान देने के पारंपरिक तरीकों के बजाय डिजिटल और आधुनिक विकल्पों की ओर बढ़ना होगा। संभावना है कि अब रिटायर कर्मचारियों को पदक के बजाय डिजिटल सर्टिफिकेट, ई-पुरस्कार या अन्य वैकल्पिक माध्यमों से सम्मानित किया जाएगा। इस कदम के पीछे मुख्य कारण चांदी की बढ़ती कीमतें और पदकों की गुणवत्ता में अनियमितता बताई जा रही है। कुछ वेंडरों द्वारा नकली या कम गुणवत्ता वाली चांदी के पदक भी कर्मचारियों तक पहुंचाए जाने की शिकायतें मिली थीं।

इस फैसले से रेलवे के वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारी निराश हैं। उनके अनुसार, यह पदक केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत और सेवा का प्रतीक था। पदक मिलने के दिन, उनके सहकर्मी और विभागीय अधिकारी उन्हें बधाई देते और यह पल उनके लिए बेहद गौरवपूर्ण होता। अब इस परंपरा के समाप्त होने से कई कर्मचारी भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं और इसे सम्मान की कमी के रूप में देख रहे हैं। रेल मंत्रालय का यह भी कहना है कि रेलवे की मौजूदा प्राथमिकताएं अब बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिक तकनीकी परियोजनाओं पर केंद्रित हैं। 'कवच' प्रणाली, वंदे भारत एक्सप्रेस और नई रेल लाइनों के निर्माण में बड़े निवेश किए जा रहे हैं। इस दिशा में खर्च को कम करना और अनावश्यक पारंपरिक गतिविधियों को रोकना आवश्यक हो गया था। सर्कुलर में यह भी साफ किया गया कि इस निर्णय का उद्देश्य केवल लागत बचत नहीं है, बल्कि रेलवे के आधुनिकीकरण और कर्मचारियों को सम्मान देने के नए तरीकों की ओर बढ़ना भी है।

'गोल्डन विदाई' योजना की शुरुआत 2006 में कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक रिटायर कर्मचारी को सोने की परत वाला चांदी का पदक दिया जाता था। यह पदक वर्षों तक रेलवे की पहचान और कर्मचारियों के लिए गौरव का प्रतीक रहा। समारोह में उनके सहकर्मी, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते और उन्हें विदाई और सम्मान देते।

अब रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि डिजिटल युग में कर्मचारियों को सम्मान देने के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। ई-गोल्डन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन प्रशंसा पत्र या अन्य डिजिटल मान्यता प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों को सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा, सेवा के वर्षों को मान्यता देने वाले अन्य पुरस्कार या छुट्टियों की सुविधा भी दी जा सकती है।

संपादकीय

मासूमों को मिले स्नेह व हौसले का संबल

पिछले दिनों फरीदाबाद में ठीक से पढ़ाई न कर सकने वाली बच्ची की पिता द्वारा पिटाई करने से हुई मौत की खबर ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोरा है। यह विश्वास करना कठिन है, कोई पिता इतना क्रूर हो सकता है कि महज गिनती न सीख पाने के कारण बच्ची की जान ले ले। यदि इस घटना के पीछे कोई परोक्ष कारण नहीं है तो निश्चय ही यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिये कलंक ही कही जाएगी। यह शर्म की बात ही है कि इस ज्ञान की सदी में किसी बच्ची की पिता के हाथों पढ़ाई के नाम पर मौत हो जाए। यह विडंबना ही है कि 21वीं सदी में भी हमारे समाज में मानसिक ग्रंथि की वह गांठ नहीं खुल पाई है, जो मानती है कि डर व मारपीट से बच्चों को सिखाया जा सकता है। ऐसी तमाम घटनाएं आज भी हमारे स्कूलों व घरों तक में सामने आती हैं। यदि स्कूल या कोचिंग में किसी बच्चे-बच्ची के साथ पढ़ाई के नाम पर आक्रामक व्यवहार होता है तो उम्मीद की जाती है कि परिवार उसके साथ मुश्किल समय में खड़ा होगा। लेकिन जब घर में माता-पिता ही हिंसक व्यवहार करने लगें तो मासूम किसके भरोसे रहेगा... कहने को देश में बच्चों के साथ होने वाले किसी भी हिंसक व्यवहार को रोकने के लिये तमाम तरह के प्रावधान सुरक्षा कवच उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब प्रवर्तन एजेंसियां ही उदासीन रहेंगी तो समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। पहले तो स्कूलों में ही ऐसे मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, फिर यदि मामला पुलिस या संबंधित विभाग के संज्ञान में आता भी है तो उसे रफा-दफा करने के प्रयास तेज हो जाते हैं। ऐसे मामलों में शिक्षक अभिभावक संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। जिसमें अकसर शिक्षण संस्था के सुर में बोलने वाले अभिभावकों को ही रखा जाता है। आज भी यह एक गंभीर समस्या है और इसके गंभीर समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है।

यह हमारे समाज की विडंबना ही कही जाएगी कि आज भी यह सोच बलवती है कि बच्चों के साथ सख्त व्यवहार से उनकी पढ़ने-लिखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जबकि हकीकत यह है कि किसी भी आक्रामक व्यवहार से बच्चों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश व दुनिया में हुए तमाम शोध व अध्ययन बताते हैं कि बच्चों के साथ सख्त व आक्रामक व्यवहार किए जाने से बच्चों की एकाग्रता व याद्दाश्त पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। जिसका नकारात्मक असर यह होता है कि बच्चे हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी कक्षा में पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। कालांतर यह भय व कुंठा जीवनभर उनका पीछा करती है। उनका आत्मविश्वास डिग जाता है। तब वे जीवन की स्पर्धा में भी दब्बू बनकर रह जाते हैं। यह भी विडंबना ही है कि आज भी बच्चों पर पढ़ाई का बोझ थोपने से पहले हमारे यहां किसी तरह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होता है कि बच्चे की अभिरुचि किन विषयों में है। सही मायनों में हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। कुदरत उसकी रचना किसी खास मकसद के लिये करती है। लेकिन मां-बाप व शिक्षक पहचान नहीं पाते कि उसका रुझान किस दिशा में है। यदि समय रहते बच्चे की उस प्रतिभा को पहचाना जा सके और उस विषय व दिशा में उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो वे अप्रत्याशित रूप से किसी भी क्षेत्र में शिखर की सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कई तरह के जन्मजात व आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, जो उनकी सामान्य पढ़ाई में बाधक हो सकता है। कई बच्चों में जन्म से ही दृष्टि दोष या कोई अन्य शारीरिक व मानसिक विकार भी हो सकता है, जिसके चलते वे अपनी पढ़ाई को ठीक से पूरा नहीं कर पाते। फलतः उन्हें शिक्षकों व परिजनों के हिंसक व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। आज बच्चों को संवेदनशील ढंग से देखने की जरूरत है ताकि उनकी पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सके।

एफटीए से यूरोप-भारत व्यापार को बूस्टर डोज़

> अब देखना होगा कि यह बहु-प्रतीक्षित समझौता भारत के 140 करोड़ और यूरोपीय संघ के 45 करोड़ लोगों हेतु कितना बड़ा अवसर लाता है। इंतज़ार रहेगा कि एफटीए का ईयू-अमेरिका व भारत-चीन के उभयपक्षीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है।

बिना एफटीए के भी यूं तो यूरोपीय देशों से भारत का व्यापार दशकों से होता आ रहा है। लेकिन, ऐसा माना गया कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने से इसे बूस्टर डोज़ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कहा, 'ईयू-इंडिया एफटीए सभी सौदों की जननी है। यह सौदा यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों का पूरक है। भारत में कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा और जूट जैसे विभिन्न क्षेत्रों को इस व्यापार समझौते से फायदा होने वाला है।' पीएम मोदी ने कहा कि यह डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करेगी, और सर्विस सेक्टर को नया सहारा देगी।

वर्ष 2007 में शुरू हुई वार्ता प्रक्रिया का समापन देर-सवेर हुआ ही। मनमोहन सिंह से आरम्भ वार्ता को मोदी ने अंजाम दिया। यहां तक पहुंचने में 19 साल लगे। लेकिन रुकिए, अभी बहुत कुछ होना बाक़ी है। सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की भाषाओं में एफटीए के कानूनी दस्तावेज़ों को प्रकाशित करना होगा। सभी धाराओं की एक-एक करके जांच होगी, जिसे 'लीगल स्क्रबिंग' कहते हैं, यूरोपीय परिषद द्वारा औपचारिक मंज़ूरी के बाद, यूरोपीय संसद की सहमति चाहिए, इसके प्रकारांतर भारतीय कैबिनेट द्वारा पुष्टि होगी। इन सबसे गुज़रने के बाद, 2027 तक इसके लागू होने की उम्मीद है।

मंगलवार को यूरोपियन कमीशन की प्रतिक्रिया ग़ौर करने लायक है— 'इस डील से ईयू कंपनियों और किसानों को ज़्यादा निर्यात करने में मदद मिलेगी। इस डील से पहले ही आठ लाख यूरोपीय नौकरियों को सपोर्ट मिलता रहा है। अब एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से, और भी ज़्यादा यूरोपीय नौकरियां मिल सकती हैं।' यूरोपियन कमीशन का सन्देश था, 'उम्मीद है कि यह समझौता भारत को होने वाले ईयू एक्सपोर्ट को दोगुना कर देगा। इसके अलावा, भारतीय सर्विस मार्केट तक बेहतर पहुंच, खासकर फाइनेंशियल

सर्विसेज़, मैरीटाइम सर्विसेज़ और दूसरे मुख्य सेक्टर्स में, नए बिज़नेस और रोज़गार के अवसर पैदा करेगी।'

यूरोपीय आयोग ने जानकारी दी, कि इस डील से 90 फीसद से ज़्यादा यूरोपीय संघ के देशों के सामानों के एक्सपोर्ट टैरिफ खत्म, या कम कर दिया जाएगा। इससे यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में हर साल अरबों यूरो तक की बचत होगी। यूरोपियन कमीशन ने कहा, 'भारत ने किसी भी व्यापारिक सहकार को इतनी बड़ी ट्रेड ओपनिंग नहीं दी है। इससे एक्सपोर्ट को तेज़ और आसान बनाने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सहज बनाया जायेगा।'

27 जनवरी को डील के तुरंत बाद यूरोपियन कमीशन ने आधिकारिक जानकारी दी कि भारत ईयू को टैरिफ में ऐसी छूट देगा, जो उसके किसी भी दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर को नहीं मिली है, जिससे ईयू एक्सपोर्ट के लिए भारतीय बाजार में पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। उदाहरण के लिए, कारों पर टैरिफ धीरे-धीरे 110 प्रतिशत से घटकर 10 फीसद हो जाएगा, जिसमें हर साल 250,000 गाड़ियों का कोटा होगा। मशीनरी पर 44 प्रतिशत, केमिकल्स पर 22 परसेंट और फार्मास्यूटिकल्स पर 11 प्रतिशत तक के ऊंचे टैरिफ को ज़ीरो पर ले आया जाएगा। टैरिफ एक टैक्स है, जो कोई देश अपने यहां विदेश से आयात होने वाले समान पर लगाता है। इससे विदेश से आने वाला सामान महंगा हो जाता है, और जिस देश में सामान आता है, उसे टैक्स से आय होता है।

यूरोपियन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर एक चार्ट के ज़रिये सारा गणित समझाया है। कमीशन ने वर्ष 2024 को आकलन का आधार बनाया, जिसमें मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण पर 16.3 बिलियन यूरो बतौर टैरिफ देने पड़े थे। एफटीए के कार्यान्वयन के बाद, यूरोपीय संघ के देशों को टैरिफ की देनदारी ज़ीरो प्रतिशत हो जाएगी। विमान और अंतरिक्ष यान निर्यात पर 11 प्रतिशत के हिसाब से 6.4 अरब यूरो टैरिफ के रूप में 2024 में देना पड़ा था, आगे से यह शून्य हो जाएगा। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण के एक्सपोर्ट पर 27.5 प्रतिशत के हिसाब से 3.4 बिलियन यूरो देना पड़ा था, इनमें से 90 फीसद प्रोडक्ट पर शून्य टैरिफ लगा करेगा। प्लास्टिक पर भी ज़ीरो टैरिफ लगा करेगा, जिससे यूरोपीय संघ के देशों को 2 अरब 20 करोड़ यूरो की बचत होगी। केमिकल्स पर 22 प्रतिशत टैरिफ आगे से शून्य हो जायेगा, उससे 3 अरब 20 करोड़ यूरो की बचत होगी। आयरन एंड स्टील पर भी 22 प्रतिशत से शून्य टैरिफ हो जाने से डेढ़ अरब और फार्मास्युटिकल्स पर टैरिफ शून्य हो जाने के बाद 1 अरब 10 करोड़ का फायदा यूरोपीय संघ के देशों को होना है।

इस डील से यूरोपीय संघ के किसानों की बल्ले-बल्ले होनी है। यूरोपियन कमीशन ने समझाया है, 'यह एग्रीमेंट ईयू से एक्सपोर्ट होने वाले एग्री-फूड प्रोडक्ट्स पर अक्सर लगने वाले बहुत ज़्यादा टैरिफ (औसतन 36 प्रतिशत से ज़्यादा) को हटाएगा या कम करेगा, जिससे यूरोपीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार खुल जाएगा। जैसे वाईन पर 150 प्रतिशत टैक्स है, उसे घटाकर प्रीमियम रेंज के वास्ते 20 परसेंट और मीडियम रेंज पर 30 फीसद टैरिफ लाने के वास्ते सहमति बन गई है। स्पिरिट्स पर टैरिफ 150 प्रतिशत से घटाकर 40 पर ले आएंगे। ईयू देशों से भारत भेजे जाने वाले बीयर पर 110 प्रतिशत टैरिफ है, उसे कम कर 50 फीसद कर देना है। जैतून का तेल, मार्जरीन और अन्य वनस्पति तेल पर जो 45 प्रतिशत टैरिफ लगता था, वो ज़ीरो हो जायेगा। कीवी और नाशपाती पर 33 से घटाकर 10 फीसद, फलों के जूस और नॉन-अल्कोहलिक बीयर पर 55 प्रतिशत टैक्स लगा करता था, आगे से ज़ीरो हो जायेगा, प्रोसेस्ड फ़ूड (ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्कुट, पास्ता, चॉकलेट, पालतू जानवरों का खाना) पर टैरिफ 50 प्रतिशत से ज़ीरो कर देंगे। भेड़ के मांस पर 33 फीसद टैरिफ लगाते थे, उसे भी ज़ीरो कर देंगे। सॉसेज और मांस से बने अन्य प्रोडक्ट्स पर जो 110 फीसद तक टैरिफ लगते थे, जब एफटीए लागू होगा, उसे 50 प्रतिशत पर ले आया जायेगा।'

ईयू और भारत, बौद्धिक संपदा अधिकारों को मजबूत करने वाले 'ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स' पर एक अलग से समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे सदस्य देशों के पारंपरिक खेती वाले उत्पादों को भारत में ज़्यादा बेचने में मदद मिलेगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन देयर लॉयेन ने कहा कि इससे दोनों पक्षों के लिए लाखों नौकरियां सृजित होंगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने हामी भरते हुए कहा कि हम दो अरब लोगों के लिए बाजार बना रहे हैं। अब देखना यह है कि यह बहु-प्रतीक्षित समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों, और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के 45 करोड़ लोगों के लिए कितना बड़ा अवसर लेकर आता है। हमें इसका भी इंतज़ार रहेगा कि इस एफटीए का ईयू-अमेरिका और भारत-चीन के उभयपक्षीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है।

प्रेरणा

सच की सुरक्षा और भयमुक्त समाज की नींव

मनुष्य के जीवन में गलती होना कोई असामान्य बात नहीं है। गलती के बिना सीख संभव नहीं और सीख के बिना विकास अधूरा है। फिर भी हमारी सामाजिक संरचना ऐसी बन गई है कि गलती को अपराध और स्वीकारोक्ति को कमजोरी मान लिया गया है। इसी मानसिकता के कारण व्यक्ति सच से दूर होता चला जाता है और धीरे-धीरे झूठ उसकी आदत बन जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक मॉन्तेन से जुड़ी वह छोटी-सी घटना इस गहरी सच्चाई को बहुत सहज ढंग से सामने रखती है कि गलती से अधिक खतरनाक होता है सच का डर।

मॉन्तेन के बगीचे में भागता हुआ घबराया हुआ नौकर केवल टूटे हुए कांच के प्याले से नहीं डर रहा था, बल्कि उस मानसिक वातावरण से भयभीत था जिसमें गलती का सीधा अर्थ सज़ा होता है। उसका डर बताता है कि वह पहले भी ऐसे अनुभवों से गुज़रा होगा या उसने दूसरों को सज़ा पाते देखा होगा। यह डर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें भय को अनुशासन का साधन माना जाता है।

मॉन्तेन ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, वह हमें सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने नौकर से यह नहीं पूछा कि प्याला कैसे टूटा या उसकी कीमत क्या थी। उन्होंने सीधे उसके डर को संबोधित किया। यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। जब हम किसी की गलती से पहले उसके डर को समझते हैं, तो हम उसे इंसान के रूप में स्वीकार करते हैं, अपराधी के रूप में नहीं। मॉन्तेन ने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान सच्चाई है।

उनका यह कथन कि "अगर हर गलती पर हम लोगों को इतना डराएं कि वे सच छुपाने लगें, तो गलती से बड़ी सच्चाई की हत्या हो जाएगी" केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। सच्चाई की हत्या अचानक नहीं होती, वह धीरे-धीरे होती है। पहले लोग छोटी बात छुपाते हैं, फिर बड़ी बातों से बचते हैं और अंततः सच बोलने की क्षमता ही खो बैठते हैं। हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि डर आधारित व्यवस्था हर जगह मौजूद है। घरों में बच्चे डांट के डर से सच नहीं बताते, स्कूलों में छात्र गलती मानने से बचते हैं, दफ्तरों में कर्मचारी रिपोर्ट छुपाते हैं और शासन-प्रशासन में अधिकारी वास्तविक स्थिति सामने रखने से हिचकिचाते हैं। परिणाम यह होता है कि समस्याएं समय रहते हल नहीं होतीं और वे विकराल रूप ले लेती हैं।

मॉन्तेन ने नौकर को दंड न देकर पूरे घर में एक नई परंपरा की नींव रखी। उन्होंने यह संदेश दिया कि यहां सच बोलना सुरक्षित है। यह सुरक्षा किसी नियम से नहीं, बल्कि विश्वास से पैदा होती है। जब व्यक्ति जानता है कि उसकी बात सुनी जाएगी और उसे समझा जाएगा, तो वह अपनी गलती स्वीकार करने में संकोच नहीं करता। यही स्वीकारोक्ति सुधार की पहली सीढ़ी बनती है।

धीरे-धीरे मॉन्तेन के घर में बदलाव आने लगा। लोग गलती छुपाने के बजाय उसे सामने लाने लगे। इससे न केवल वातावरण हल्का हुआ, बल्कि सीखने की प्रक्रिया भी तेज़ हुई। हर गलती एक सबक बन गई और हर सबक सामूहिक समझ का हिस्सा। यह वही प्रक्रिया है जो किसी भी स्वस्थ समाज या संगठन को आगे बढ़ाती है।

दुर्भाग्य से आज हम उलटी दिशा में चल रहे हैं। हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां दिखावा सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लोग सही होने का अभिनय करते हैं, भले ही भीतर से वे गलतियों में उलझे हों। यह दिखावा व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। मॉन्तेन की सोच हमें इस खोखलेपन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है।

गलती और व्यक्ति के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। गलती एक कार्य है, व्यक्ति की पहचान नहीं। जब हम व्यक्ति को उसकी गलती से जोड़ देते हैं, तो हम उसे सुधारने का अवसर छीन लेते हैं। मॉन्तेन ने इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझा और यही उनकी महानता है। उन्होंने नौकर को यह एहसास दिलाया कि वह अपनी गलती से बड़ा है।

यह विचार केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि यही सोच शिक्षा प्रणाली में आए, तो बच्चे रटने के बजाय सीखने लगेंगे। यदि यही सोच कार्यस्थलों पर लागू हो, तो नवाचार बढ़ेगा और डर कम होगा। यदि यही सोच शासन में आए, तो पारदर्शिता और जवाबदेही अपने आप मजबूत होगी।

मॉन्तेन का यह कथन कि "जहां सच बोलने पर सज़ा मिलती है, वहां झूठ पनपता है" मानव स्वभाव की गहरी समझ को दर्शाता है। झूठ कोई स्वाभाविक गुण नहीं, बल्कि भय की प्रतिक्रिया है। जैसे ही भय हटता है, झूठ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसलिए यदि हमें ईमानदार समाज चाहिए, तो हमें सबसे पहले डरमुक्त वातावरण बनाना होगा।

अंततः यह कहानी हमें आत्ममंथन का अवसर देती है। हमें यह सोचना होगा कि हम अपने आसपास कैसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हम गलती को सीख का अवसर मानते हैं या उसे अपमान का कारण बना देते हैं? कांच का प्याला टूटना एक छोटी घटना थी, लेकिन उस पर दी गई प्रतिक्रिया ने सच्चाई, विश्वास और मानवीय गरिमा की बहुत बड़ी सीख दे दी।सच बोलने का साहस तभी पनपता है जब सामने वाला सुनने और समझने का साहस रखता हो। मॉन्तेन ने यह साहस दिखाया और यही साहस आज भी हर घर, हर संस्था और हर समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

समता और समावेशन की दिशा में सार्थक पहल

यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने इस संबंध में समिति के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है। यह पहल किसी राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से सामने आ रही सामाजिक विसंगतियों और न्यायिक हस्तक्षेप का नतीजा है।

यूजीसी ने फरवरी, 2025 में 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम, 2026' का मसौदा जारी किया था। इसके बाद यह मसौदा संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की। 8 दिसंबर, 2025 को समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आंकड़ों और तथ्यों के साथ यह स्पष्ट किया गया कि देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल एससी और एसटी ही नहीं, बल्कि ओबीसी विद्यार्थियों के साथ भी जातिगत भेदभाव की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर 13 जनवरी, 2026 को यह विनियम राजपत्र में प्रकाशित हुआ और 15 जनवरी, 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया गया।

इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट और संवैधानिक है—धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान अथवा दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में समता, न्याय और समावेशन को सुनिश्चित करना। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन वर्गों के लिए बनाई गई है, जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, शैक्षणिक और संस्थागत स्तर पर अन्याय होता रहा है।

इसके बावजूद इस प्रावधान का विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों का प्रमुख तर्क यह है कि इस समिति में 'जनरल कैटेगरी' को शामिल नहीं किया गया, इसलिए यह नियम भेदभावपूर्ण है। लेकिन यह प्रश्न विचारणीय है कि जाति-आधारित भेदभाव सामान्य वर्ग के साथ किस प्रकार होता है। जब देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, प्राचार्य और कुलपति पदों पर लगभग 97 प्रतिशत प्रतिनिधित्व उन्हीं वर्गों का है, तब निर्णय, मूल्यांकन और प्रशासनिक सत्ता पहले से ही उनके हाथों में है। ऐसे में उनके साथ जातिगत उत्पीड़न की आशंका वस्तुतः तथ्य से अधिक आशंका और भ्रम पर आधारित प्रतीत होती है।

विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के दुष्परिणामों का इतिहास नया नहीं है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अपने अंतिम पत्र में उन्होंने लिखा था— 'मेरा जन्म ही एक दुर्घटना था।' इसके बाद पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे कई मामले सामने आए। ये घटनाएं केवल व्यक्तिगत त्रासदियां नहीं हैं, बल्कि उस व्यवस्था की ओर संकेत करती हैं, जहां शिक्षा के केंद्र ही उत्पीड़न के स्थल बनते चले गए।

यह भी एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि यदि कोई ओबीसी विद्यार्थी किसी एससी या एसटी विद्यार्थी के साथ भेदभाव करेगा, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। विनियम इस संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट है। किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा किया गया जाति-आधारित भेदभाव जांच के दायरे में आएगा। समिति का उद्देश्य किसी को पूर्वाग्रह के आधार पर दोषी ठहराना नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करना है।

समिति की संरचना भी संतुलित और प्रतिनिधिक रखी गई है। इसमें संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, वरिष्ठ संकाय सदस्य, कर्मचारी प्रतिनिधि, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि और सचिव शामिल होंगे। साथ ही यह अनिवार्य किया गया है कि समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व हो। यह व्यवस्था इसलिए आवश्यक है ताकि निर्णय प्रक्रिया समावेशी और एकतरफा प्रभाव से मुक्त रहे।

विरोध का एक और तर्क संभावित 'दुरुपयोग' को लेकर दिया जा रहा है। किंतु यह तर्क स्वयं में कमजोर है। महिलाओं के लिए बने कानूनों, श्रम कानूनों या आतंकवाद विरोधी कानूनों के दुरुपयोग की आशंका के बावजूद उन्हें समाप्त नहीं किया गया। किसी कानून के संभावित दुरुपयोग के डर से न्याय के रास्ते बंद कर देना स्वयं अन्याय को बढ़ावा देना है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जिन समुदायों के विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए यह प्रावधान बनाया गया है, उनमें इसके प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है। दूसरी ओर, सांस्कृतिक और संस्थागत वर्चस्व रखने वाले वर्ग संगठित रूप से मीडिया, सोशल मीडिया और न्यायिक मंचों पर इसका विरोध कर रहे हैं। यह प्रावधान कोई 'काला कानून' नहीं, बल्कि संविधान में निहित समानता और गरिमा के मूल्यों को व्यवहार में उतारने का प्रयास है। जैसे कार्यस्थलों और शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए वूमेन सेल आवश्यक माने जाते हैं, उसी प्रकार जातिगत भेदभाव से पीड़ित वर्गों के लिए यह समिति आवश्यक है। यदि आज इसे कमजोर किया गया, तो भविष्य में फिर किसी रोहित, किसी पायल या किसी दर्शन को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वक्त की मांग है कि हम न्याय, समानता और समावेशन के पक्ष में खड़े होकर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित-समान अवसरों वाले भविष्य सुनिश्चित करें।

अभियान

बजरंगबली की मौन कृपा: गुप्त भक्ति से कैसे जागृत होती है अदृश्य शक्ति

सनातन परंपरा में हनुमान जी केवल एक पूज्य देवता नहीं हैं, बल्कि वे चेतना, साहस, सेवा और निस्वार्थ समर्पण की जीवित परिभाषा माने जाते हैं। उन्हें संकटमोचन कहा गया है, क्योंकि वे न केवल जीवन की बाहरी बाधाओं को हरते हैं, बल्कि मनुष्य के भीतर बैठे भय, संशय, आलस्य और नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी जड़ से समाप्त कर देते हैं। कलियुग में हनुमान जी की उपासना को विशेष महत्व इसलिए दिया गया है, क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और सच्चे भाव से की गई साधना का फल तुरंत देते हैं। शास्त्रों और लोकमान्यताओं में बार-बार यह संकेत मिलता है कि हनुमान जी को दिखावे से भरी पूजा नहीं, बल्कि मौन, गुप्त और निस्वार्थ भक्ति अत्यंत प्रिय है।

गुप्त भक्ति का अर्थ केवल चुपचाप पूजा करना नहीं है, बल्कि उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां साधक का अहंकार समाप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी को बताए, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के, केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ अर्पित करता है, तब वह सीधा हनुमान जी की चेतना से जुड़ता है। यही कारण है कि गुप्त दान, गुप्त सेवा और गुप्त जप को हनुमान साधना में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ऐसी भक्ति में ऊर्जा का क्षय नहीं होता, बल्कि वह भीतर ही भीतर सघन होकर जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने लगती है।

लौंग को भारतीय पूजा परंपरा में शुद्धिकरण और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। लौंग के भीतर अग्नि तत्व की सूक्ष्म शक्ति मानी जाती है, जो नकारात्मकता को नष्ट करने में सक्षम होती है। जब कोई भक्त मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुप्त रूप से एक या दो साबुत लौंग उनके चरणों में रख देता है, तो यह साधारण सा कर्म एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय जीवन में फैली अदृश्य बाधाओं को हटाने में सहायक होता है। जिन लोगों को बिना कारण भय लगता है, जिनके कार्य बार-बार अटक जाते हैं या जिनका मन अशांत रहता है, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से फलदायी माना गया है। लौंग अर्पित करने वाला भक्त अनजाने ही अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर देता है और उसके जीवन में शांति व सौभाग्य का प्रवेश होने लगता है।

माचिस जैसी साधारण वस्तु का हनुमान साधना में विशेष महत्व बताया गया है। माचिस अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हनुमान जी स्वयं तेज, ऊर्जा और अग्नि के प्रतीक माने जाते हैं। जब कोई भक्त गुप्त रूप से हनुमान जी को माचिस अर्पित करता है, तो यह एक प्रतीकात्मक प्रार्थना होती है कि मेरे भीतर की दुर्बलता, भय, आलस्य और हीनभावना अग्नि में जलकर समाप्त हो जाए। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है, जो आत्मविश्वास की कमी, निर्णयहीनता या ऊर्जा के अभाव से जूझ रहे हों। माचिस का गुप्त दान यह संकेत देता है कि साधक अपने भीतर प्रकाश चाहता है, अंधकार नहीं। मान्यता है कि इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में तेजस्विता आती है और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है।

तुलसी का स्थान सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी को माता का दर्जा प्राप्त है और भगवान विष्णु व उनके अवतार श्रीराम को तुलसी अति प्रिय है। हनुमान जी तो स्वयं श्रीराम के परम भक्त हैं, इसलिए तुलसी अर्पण का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जब कोई भक्त हनुमान जी के चरणों में गुप्त रूप से तुलसी की कुछ पत्तियां अर्पित करता है, तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि वह राम कृपा से सीधा जुड़ाव बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की उपस्थिति वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। यह उपाय विशेष रूप से स्वास्थ्य, मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना गया है। गुप्त रूप से किया गया तुलसी अर्पण व्यक्ति की भक्ति को सात्त्विक बनाता है और उसके जीवन में स्थिरता लाता है।

हनुमान जी की सबसे बड़ी साधना उनका राम नाम में अटूट विश्वास है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी स्वयं राम नाम के जप से संचालित होते हैं। इसलिए किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक शक्तिशाली उपाय है गुप्त रूप से राम नाम का जाप। जब कोई साधक हनुमान जी के सामने बैठकर मन ही मन "राम" नाम का स्मरण करता है, बिना किसी को बताए, बिना ऊंचे स्वर में, तब वह एक गहरी आंतरिक साधना में प्रवेश करता है। यह गुप्त जप साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शत्रु भय, मानसिक तनाव, अनिद्रा और अकारण भय से मुक्ति मिलती है। राम नाम का मौन जप आत्मा को स्थिर करता है और व्यक्ति को भीतर से निर्भीक बनाता है।

पीले रंग को शुभता, ज्ञान और गुरु तत्व का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में पीला रंग गुरु ग्रह से जुड़ा होता है, जो विवेक, धर्म और सद्बुद्धि का कारक है। हनुमान जी को गुप्त रूप से पीला वस्त्र अर्पित करने से साधक के जीवन में विवेक और समझ का विकास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है, जिनके जीवन में पारिवारिक कलह, आर्थिक अस्थिरता या निर्णय संबंधी भ्रम बना रहता है। पीला वस्त्र बिना किसी दिखावे के हनुमान जी के मंदिर में रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे गुरु कृपा मजबूत होती है, धन-संपत्ति में वृद्धि होती है और गृह क्लेश समाप्त होने लगते हैं। इस उपाय से जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव होता है।

इन सभी उपायों का मूल भाव एक ही है—निस्वार्थता और मौन समर्पण। हनुमान जी को वही भक्ति प्रिय है जिसमें साधक स्वयं को पूरी तरह विसर्जित कर देता है। गुप्त भक्ति में अहंकार नहीं होता, इसलिए उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जब व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कुछ अर्पित करता है, तब वह स्वयं उस आशीर्वाद के योग्य बन जाता है। ऐसे उपाय धीरे-धीरे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, जो केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होते हैं।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि हनुमान जी की कृपा केवल संकट टालने तक सीमित नहीं है। उनकी कृपा मनुष्य को भीतर से इतना सशक्त बना देती है कि वह संकटों से भयभीत होना ही छोड़ देता है। गुप्त साधना और मौन भक्ति व्यक्ति के चरित्र, सोच और कर्मों को शुद्ध करती है। जब भीतर की शक्ति जागृत होती है, तब बाहरी बाधाएं स्वतः कमजोर पड़ जाती हैं। यही बजरंगबली की मौन कृपा है, जो दिखती नहीं, लेकिन जीवन को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेताया: लावारिस कुत्तों पर कार्रवाई सिर्फ हवा-हवाई, धरातल पर कोई असर नहीं

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत में लावारिस कुत्तों की बढ़ती आबादी और उनसे जुड़े खतरे को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकांश राज्य सरकारें कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, शेल्टर और बढ़ती काटने की घटनाओं के संबंध में केवल 'हवा-हवाई बातें' कर रही हैं, जबकि धरातल पर ठोस कार्रवाई न के बराबर है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आंकड़े, मानव संसाधन और स्पष्ट कार्ययोजना के बिना गोलमोल दावे पेश किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने गहन निरीक्षण में पाया कि अधिकांश राज्य सरकारें पिछले आदेशों का पालन करने के बजाय सिर्फ रिपोर्ट में कथित उपलब्धियों का हवाला दे रही हैं। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि हलफनामों से साफ पता चलता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अस्पष्ट और मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर रहे हैं। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसे हालात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और भविष्य में अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार के आंकड़े भी अदालत के लिए संतोषजनक नहीं थे। पीठ ने नोट किया कि पिछले आठ महीनों में मात्र 68,000 कुत्तों की नसबंदी की गई, जो आबादी नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है। न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि इस साल दिल्ली में नसबंदी की संख्या दोगुना करने की आवश्यकता है, ताकि बढ़ती आबादी और काटने की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। अदालत ने इस दिशा में स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राज्य अपनी नसबंदी क्षमता बढ़ाएं और प्रभावी कार्य योजना पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा पेश आंकड़ों पर भी संदेह व्यक्त किया। झारखंड ने दावा किया कि 1,89,000

कुत्तों की नसबंदी की गई है, लेकिन अदालत ने पाया कि वास्तविक संख्या सिर्फ 1.60 लाख है और वह भी महज दो महीनों में की गई। पीठ ने कहा कि इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है।
बिहार की स्थिति भी निराशाजनक पाई गई। राज्य ने दावा किया कि 34 पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों में 20,648 कुत्तों की नसबंदी की गई है, लेकिन अदालत ने नोट किया कि राज्य ने नसबंदी की दैनिक क्षमता और समयावधि का विवरण नहीं दिया। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि राज्य केवल हवा में महल बना रहा है और वास्तविक कार्यवाही धरातल पर नहीं दिख रही। अदालत ने बिहार को निर्देश दिया कि सभी एबीसी केंद्रों का ऑडिट किया जाए और कार्य योजना को स्पष्ट किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सार्वजनिक इमारतों में कुत्तों के लिए बाड़ लगाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि स्कूलों और अस्पतालों में बाड़ लगाने के आदेशों का पालन नहीं किया गया है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की गई, जिसने कुत्तों के काटने, नसबंदी और टीकाकरण पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अच्छी शुरुआत बताते हुए अन्य राज्यों को भी इसी तरह के प्रभावी उपाय करने के लिए कहा। वहीं, असम सरकार के आंकड़े चौंकाने वाले पाए गए। अदालत ने बताया कि 2024 में 1,66,000 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए, जबकि 2025 के केवल जनवरी महीने में 20,900 मामले दर्ज किए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में पर्याप्त एबीसी केंद्र नहीं हैं और सरकार के पास संख्या बढ़ाने की विस्तृत योजना होनी चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि केवल आंकड़े पेश करने से काम नहीं चलेगा, ठोस और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।
इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी, जिसमें पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना द्वारा उठाए गए कदमों पर पीठ विचार करेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि लावारिस कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी मामला है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी से स्पष्ट है कि अब राज्यों के पास बहाने बनाने का समय नहीं है। उन्हें या तो धरातल पर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी या फिर न्यायालय की कठोर निगरानी और निर्देशों का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में अदालत का उद्देश्य न केवल लावारिस कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि मानव जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

नई आधार ऐप से डिजिटल पहचान और भी आसान और सुरक्षित बन गई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अब आधार से जुड़े काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्रीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर नई आधार ऐप को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिया है। इस ऐप का ऐलान पहली बार नवंबर 2025 में किया गया था और अब यह आम उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई है। नई आधार ऐप का उद्देश्य सिर्फ डिजिटल पहचान को मजबूत करना ही नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ताओं की सुविधा और सुरक्षा को भी नई ऊंचाई पर ले जाना है।
नई ऐप के माध्यम से अब उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन से ही आधार से जुड़े कई काम आसानी से कर सकेंगे। इसमें अपना आधार नंबर सत्यापित करना, डिजिटल आधार आईडी की जांच करना, आधार से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से साझा करना और कई सरकारी और निजी सेवाओं के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण करना शामिल है। इससे भौतिक आधार कार्ड पर निर्भरता कम होगी और दस्तावेजों की कॉपी देने की आवश्यकता घटेगी।
सामान्यतः होटल चेक-इन, सिम कार्ड लेने या बैंकिंग सेवाओं के लिए आधार की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा बना रहता था। नई आधार ऐप इस जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐप के माध्यम से अब डिजिटल तरीके से सत्यापन किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
केंद्रीय अधिकारियों ने बताया कि नई ऐप यूजर फ्रेंडली डिजाइन के साथ तैयार की गई है और इसमें बायोमेट्रिक और ओटीपी आधारित सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना आपके मोबाइल और बायोमेट्रिक अनुमति के आपके आधार डेटा तक पहुँच नहीं बना सकेगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया पहल को और सशक्त बनाएगा। आधार का उपयोग अब केवल पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में डिजिटल ट्रांजैक्शन और प्रमाणीकरण का एक मजबूत माध्यम बन जाएगा।
इसके अलावा, नई ऐप से उपयोगकर्ता अपनी आधार संबंधी जानकारी को अपडेट कर सकेंगे, पते बदलने और अन्य विवरणों में सुधार करने की सुविधा भी पाएंगे। पहले यह प्रक्रिया काफी समय लेने वाली और जटिल मानी जाती थी, लेकिन नई ऐप इसे सरल और सुरक्षित बना देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल पहचान के मामले में यह नई ऐप एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल डेटा की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि लोगों की आधार से जुड़े कामकाज में तेजी और पारदर्शिता भी आएगी।

भारत- ईयू एफटीए, माननीय प्रधानमंत्री की दूर की सोच वाली लीडरशिप में एक बड़ी कामयाबी; निर्यात प्रतिस्पर्धा को बदलने और वैश्विक वैल्यू चेन के साथ भारत के एकीकरण को गहरा करने के लिए तैयार: फियो अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन

(जीएनएस)। नई दिल्ली; 27 जनवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) ने भारत-यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता (भारत- ईयू एफटीए) के ऐतिहासिक ऐलान के बाद, भारत के माननीय प्रधानमंत्री की दूर की सोच वाली लीडरशिप, दूर की स्ट्रेटेजिक सोच और फैसले लेने वाली डिप्लोमेसी की दिल से तारीफ़ की है। इस ऐतिहासिक समझौते का ऐलान आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट महामहिम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने नई दिल्ली में हुए 16वें भारत- ईयू समिट में मिलकर किया। भारत - ईयू एफटीए का पूरा होना भारत की वैश्विक इकोनॉमिक यात्रा में एक अहम पड़ाव है और यह व्यापार से होने वाली ग्रोथ, इकोनॉमिक सुधारों और वैश्विक एकीकरण के लिए भारत सरकार के पक्के प्रतिबद्धता का सबूत है। यह समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन को भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर मज़बूत करता है, जो खुले बाज़ार, पहले से तय और सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध हैं। फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि यह 2022 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद से सरकार के मज़बूत राजनीतिक इरादे के साथ लगातार, नतीजे पर आधारित बातचीत का नतीजा है, जो एक संतुलित, मॉडर्न और नियमों पर आधारित इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाने के साझा नज़रिए को दिखाता है।
यूरोपियन यूनियन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। वित्त वर्ष 2024–25 में, भारत - ईयू का वस्तु का आपसी व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये (136.54 बिलियन डॉलर) था, जिसमें 6.4 लाख करोड़ रुपये (75.85 बिलियन डॉलर) का निर्यात और 5.1 लाख करोड़ रुपये (60.68 बिलियन डॉलर) का इंपोर्ट शामिल था। सेवा क्षेत्र में व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपये (83.10 बिलियन डॉलर) तक पहुँच गया। भारत और ईयू मिलकर दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हैं, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा हैं—यह एक ऐसा अवसर है जिसे भारत सरकार ने इस बदलाव लाने वाले एग्रीमेंट के ज़रिए स्ट्रेटेजिक तरीके से खोला है।
श्री रल्हन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के डायनैमिक और रिफॉर्म-ओरिएंटेड लीडरशिप में भारत- ईयू एफटीए का सफल होना एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है, जो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ाएगा और वैश्विक वैल्यू चेन के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देगा। यह एग्रीमेंट भारतीय निर्यातकों के लिए वस्तु और सेवा क्षेत्र में, खासकर लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स, एमएसएमई, महिला एंटरप्रेन्योर्स, कारीगरों और युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए पहले कभी नहीं देखा गया मार्केट एक्सेस खोलता है—जो सरकार के इनक्लूसिव ग्रोथ एजेंडा के मुख्य फोकस एरिया हैं।
उन्होंने कहा कि लगभग 33 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात पर 10 प्रतिशत तक टैरिफ खत्म होने से, एफटीए टेक्सटाइल, कपड़े, लेदर, फुटवियर, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, मरीन प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल जैसे खास सेक्टर को तुरंत और ठोस फायदा देगा। इन फायदों से ज़्यादा निर्यात, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा और वैश्विक व्यापार में जमीनी स्तर पर मजबूत भागीदारी होगी, जिससे निर्यात से होने वाली खुशहाली के सरकार के विजन को मजबूती मिलेगी।
इस समझौते में वस्तु और सेवा क्षेत्र का व्यापार, ओरिजिन के नियम, कस्टम में आसानी, व्यापार उपचारों और डिजिटल व्यापार और एमएसएमई जैसे उभरते हुए सेक्टर पूरी तरह से शामिल हैं। इसमें नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए मजबूत सिस्टम शामिल हैं – जो बेहतर रेगुलेटरी सहयोग, ट्रांसपेरेंट एसपीएस उपायों और आसान कस्टम प्रोसेस के ज़रिए ईयू रेगुलेटर्स के साथ सरकार के प्रोएक्टिव जुड़ाव का नतीजा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सोच-समझकर और कोटा- आधारित लिबरलाइजेशन से ईयू मैन्युफैक्चरर्स को भारत में एडवांस्ड मॉडल पेश करने की इजाज़त मिलेगी, साथ ही सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के साथ जुड़े भविष्य के मौके भी बनेंगे।
भारतीय उपभोक्ताओं को हाई-टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तक बेहतर एक्सेस और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से फायदा होने की उम्मीद है। चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड्स के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस के साथ एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा, जबकि सरकार ने डेयरी और अनाज जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को समझदारी से सुरक्षित रखा है, जिससे किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।
एफटीए आईटी/आईटीईएस , प्रोफेशनल सर्विसेज़, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज़, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और दूसरी बिजनेस सर्विसेज़ सहित सर्विसेज़ में कमर्शियली सार्थक प्रतिबद्धता देता है। 144 ईयू सब-सेक्टर्स में अनुमानित मार्केट एक्सेस भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अवसरों को काफी बढ़ाएगा, जबकि रेसिप्रोकल एक्सेस भारत में हाई-टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा। प्रोग्रेसिव मोबिलिटी प्रोविजन्स भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वैश्विक अवसरों को प्राप्त करने के लिए सरकार की लगातार कोशिशों को दिखाते हैं, जिसमें शॉर्ट-टर्म बिजनेस ट्रैवल, इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विस सप्लायर्स, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स और डिपेंडेंट्स के लिए काम के अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा, भारत ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर्स को ईयू सदस्य देशों में अपने टाइटल के तहत काम करने की मान्यता दिलाई है, जहाँ ऐसे तरीकों को रेगुलेट नहीं किया जाता है - यह एक महत्वपूर्ण राजनयिक और सांस्कृतिक उपलब्धि है जो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह समझौता टीआरआईपीएस के तहत बौद्धिक संपदा सुरक्षा को मजबूत करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को मान्यता देता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें सीबीएएम कंप्लायंस से संबंधित सहायता भी शामिल है।
श्री रल्हन ने दोहराया कि भारत- ईयू एफटीए, सरकार के हाल ही में ब्रिटेन और ईएफटीए के साथ हुए एफटीए के साथ मिलकर, भारतीय निर्यातकों के लिए पूरे यूरोपीय बाजार को प्रभावी ढंग से खोलता है, जो भारत की व्यापार कूटनीति में एक रणनीतिक सफलता है। यह ऐतिहासिक समझौता 'विकसित भारत 2047' के विजन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, और भारत को एक लचीले, प्रतिस्पर्धी और दूरदर्शी वैश्विक व्यापार नेता के रूप में स्थापित करता है।
भारत- ईयू एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव में एक नए युग की शुरुआत करता है, जो भारत सरकार की रणनीतिक स्पष्टता, बातचीत की ताकत और दीर्घकालिक विजन को दर्शाता है - 27-सदस्यीय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है, साथ ही भविष्य की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नींव रखता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियम पर सुनवाई की मंजूरी दी, जाति आधारित विवाद पर लगी नजर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा हाल ही में अधिसूचित नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। यह याचिका उन नियमों की आलोचना करती है, जिनमें दावा किया गया है कि जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा संकीर्ण और कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर करने वाली है। चीफ जस्टिस डी.वाई. सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमलाल बागची की पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह सुनवाई सुनिश्चित करेगी कि नियमों में मौजूद खामियों को समय रहते ठीक किया जाए।
याचिका दायर करने वाले पक्ष ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए इस नए नियम में कई पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को संस्थागत लाभों से बाहर रखा गया है। उनके अनुसार, नियम में जाति आधारित विशेष प्रावधानों की परिभाषा इतनी संकीर्ण है कि वह समाज के कई हिस्सों को लाभ लेने से रोकती है। वकील ने यह भी कहा कि इस नियम के कारण उच्च शिक्षा में समान अवसर के सिद्धांत को खतरा है और यह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत निषिद्ध भेदभाव को जन्म दे सकता है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि खामियों को दूर किया जाए। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।" इस टिप्पणी से संकेत मिलता है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वर्ग के साथ अनुचित भेदभाव न हो। जस्टिस बागची ने भी कहा कि उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और यदि नियमों में किसी तरह की संवैधानिक असंगति है, तो उसे समय रहते ठीक किया जाना चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में जाति आधारित आरक्षण और संस्थागत संरक्षण की जटिलताओं को उजागर करता है। पिछले कुछ वर्षों में, UGC ने कई नए नियम और दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों में समान अवसर सुनिश्चित करना है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इन नियमों ने कई पिछड़े और कमजोर वर्गों को लाभ से बाहर करने का रास्ता खोल दिया है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नए नियम में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा इतनी सीमित है कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अलावा कई उपवर्गों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उच्च शिक्षा के अवसरों में असमानता बढ़ सकती है और सामाजिक समावेशन का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा।
UGC की ओर से पेश पक्ष ने कोर्ट को यह तर्क दिया कि नियम का उद्देश्य केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार, किसी भी वर्ग को लक्षित रूप से बाहर करना नियम का उद्देश्य नहीं था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि नियम का व्यवहारिक प्रभाव क्या होगा और क्या यह संविधान के समावेशी सिद्धांतों के अनुरूप है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर सुनवाई की मंजूरी से संकेत मिलता है कि उच्च शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण और संस्थागत संरक्षण के मुद्दे पर व्यापक सार्वजनिक और न्यायिक ध्यान दिया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला देश के उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने में निर्णायक साबित हो सकता है।

उत्तराखंड में विकास और हरित ऊर्जा को नई रफ्तार, कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति सहित आठ अहम फैसलों पर लगाई मुहर

(जीएनएस)। देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक साथ कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 'उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति–2026' समेत कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को राज्य के दीर्घकालिक विकास, निवेश आकर्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
मंत्रिमंडल बैठक की शुरुआत शोक संवेदना के साथ हुई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और हाल ही में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कैबिनेट ने दो मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है और अजित पवार का सार्वजनिक जीवन समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की।
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई हाइड्रोजन नीति को मंजूरी देना रहा। सरकार का मानना है कि इस नीति से उत्तराखंड को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नीति के तहत प्रोत्साहन, सब्सिडी और अन्य सुविधाओं से जुड़े निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि प्रक्रिया सरल और प्रभावी रहे।
कैबिनेट ने सामरिक और नागरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक और बड़ा फैसला लेते हुए उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ और चमोली के गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है। इससे सीमावर्ती और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत होगी और सेना के साथ-साथ आम नागरिकों को भी बेहतर हवाई सुविधा मिल सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने सेवाकाल में एक बार आपसी सहमति से स्थानांतरण की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। लंबे समय से कर्मचारियों की यह मांग थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।
इसके साथ ही विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए आपसी सहमति से सीधे भूमि क्रय का अधिकार भी सरकार ने प्रदान किया है। इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी कम होने और विवादों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
जनजातीय क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में भी कैबिनेट ने कदम बढ़ाया है। बैठक में चार नए जनजाति कल्याण अधिकारी पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई, जिससे दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। वहीं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उधमसिंहनगर जिले में स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि सिडकुल को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इसके अलावा औद्योगिक पट्टों से संबंधित नियमावली में संशोधन कर उप-पट्टे की व्यवस्था को सरल बनाया गया है, ताकि निवेशकों को अधिक सहूलियत मिल सके। भूजल के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिससे संसाधनों का संतुलित और नियंत्रित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जीआरडी उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी गई है, जिससे उच्च शिक्षा के नए अवसर राज्य में उपलब्ध होंगे।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में हुई इस कैबिनेट बैठक के फैसलों को उत्तराखंड के लिए विकास, निवेश, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों का संतुलित रोडमैप माना जा रहा है।

सोना वायदा में 6000 रुपये और चांदी वायदा में 20456 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 52 रुपये बढ़ा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 237851.87 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 88522.86 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 149323.3 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 46600 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3908.54 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 77878.03 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 159900 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 164900 रुपये और नीचे में 159900 रुपये पर पहुंचकर, 157699 रुपये के पिछले बंद के सामने 6000 रुपये या 3.8 फीसदी बढ़कर 163699 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 2036 रुपये या 1.5 फीसदी की तेजी के संग 137689 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 287 रुपये या 1.69 फीसदी की तेजी के संग 17248 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी फरवरी वायदा 159296 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 164748 रुपये और नीचे में 159296 रुपये पर पहुंचकर, 5349 रुपये या 3.37 फीसदी की तेजी के संग 164093 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 167099 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 170500 रुपये और नीचे में 167099 रुपये पर पहुंचकर, 166335 रुपये के पिछले बंद के सामने 3512 रुपये या 2.11 फीसदी की तेजी के संग 169847 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 364821 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 383100 रुपये और नीचे में 364821 रुपये पर पहुंचकर, 356279 रुपये के पिछले बंद के सामने 20456 रुपये या 5.74 फीसदी बढ़कर 376735 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 20594 रुपये या 5.69 फीसदी की मजबूती के साथ 382777 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 20600 रुपये या 5.69 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 382772 रुपये प्रति किलो पर आ गया। मेटल वर्ग में 6194.00 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 88522.86 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 149323.3 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 77878.03 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 46600 पॉइंट के स्तर पर

वायदा 14.65 रुपये या 1.12 फीसदी की तेजी के संग 1322.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि जस्ता फरवरी वायदा रु.9.9 या 3.05 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 334.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 5.1 रुपये या 1.6 फीसदी की मजबूती के साथ 323.8 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 30 पैसे या 0.16 फीसदी चढ़कर 191.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3907.74 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5755 रुपये के भाव पर खूलकर, 5797 रुपये के दिन के उच्च और 5713 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 52 रुपये या 0.91 फीसदी की मजबूती के साथ 5757 रुपये प्रति बैरल बोला गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 57 रुपये या 1 फीसदी बढ़कर 5761 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 350.3 रुपये के भाव पर खूलकर, 350.3 रुपये के दिन के उच्च और 329.1 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 352.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 16 रुपये या 4.53 फीसदी की गिरावट के साथ 336.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 15.8 रुपये या 4.48 फीसदी घटकर 337 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।
कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 1022 रुपये के भाव पर खूलकर, 1.4 रुपये या 0.14 फीसदी की मजबूती के साथ 1009.9 रुपये प्रति किलो बोला गया।
कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 48407.75 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 29470.28 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4867.56 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 625.93 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 30.34 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 670.17 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 788.21 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3104.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19666 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 103755 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 38760 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 404235 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 71047 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14317 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 35743 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 98610 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21148 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 22460 लोट के स्तर पर था।
इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 45500 पॉइंट पर खूलकर, 46800 के उच्च और 45500 के नीचले स्तर को छूकर, 1642 पॉइंट बढ़कर 46600 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।
कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 37.4 रुपये की बढ़त के साथ 268.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.85 रुपये की गिरावट के साथ 33.55 रुपये हुआ।
सोना फरवरी 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2529.5 रुपये की बढ़त के साथ 8733.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 330000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 11964 रुपये की बढ़त के साथ 62900 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.38 रुपये की बढ़त के साथ 35.11 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.82 रुपये की बढ़त के साथ 19.45 रुपये हुआ।
पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 23.5 रुपये की गिरावट के साथ 246.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.3 रुपये की बढ़त के साथ 17.15 रुपये हुआ।
सोना फरवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 482.5 रुपये की गिरावट के साथ 1222 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4972.5 रुपये की गिरावट के साथ 8500 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.6 रुपये की गिरावट के साथ 16.08 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 10 पैसे के सुधार के साथ 5.05 रुपये हुआ।

पंजाब की AAP सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मानजी का अहमदाबाद में आगमन

- गुजरात में AAP का संगठन मजबूत, गांव-गांव और शहरों में बड़ी-बड़ी सभाएं हो रही हैं: भगवंत मान
- विसावदर उपचुनाव में गोपाल इटालिया की जीत एक बड़ा संकेत: भगवंत मान
- अरविंद केजरीवालजी का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, जिसे पंजाब में भी लागू किया गया है, उसे गुजरात में भी लागू करेंगे: भगवंत मान
- SIR की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को सामने आकर संतोषजनक कदम उठाने चाहिए: भगवंत मान
- SIR द्वारा यदि नकली जनता बनाई जाती रही तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा?: भगवंत मान
- UGC मुद्दे पर यदि कोई सवाल उठ रहे हैं तो उस पर संतोषजनक निरीक्षण होना चाहिए: भगवंत मान
- पंजाब ने सबसे अधिक बलिदान दिए हैं और अनाज की कमी के समय ग्रीन रिवोल्यूशन में भी पंजाब का बड़ा योगदान रहा, फिर भी आज तक पंजाब के पास अपनी राजधानी नहीं है: भगवंत मान
- महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवारजी की आत्मा को भगवान शांति दे: भगवंत मान

(जीएनएस)। अहमदाबाद/गुजरात। पंजाब की AAP सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मानजी का आज शाम अहमदाबाद में आगमन हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी, विधायक गोपाल इटालिया, विधायक चैतर वसावा, प्रदेश संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता डॉ. करन बारोट सहित बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार का एक गंभीर दुर्घटना में निधन हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वर्तमान में गुजरात में हमारी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत रूप से खड़ा हुआ है। गांव-गांव जनसभाएं हो रही हैं और बड़े शहरों में भी लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है। अब तक जो माहौल हमने देखा है, उससे स्पष्ट होता है कि गुजराती जनता कुछ नया चाहती है। कांग्रेस तो यहां लगभग नजर ही नहीं आती। विसावदर से गोपाल इटालिया की शानदार जीत और वह भी बड़े मार्जिन से, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है और हम और अधिक मेहनत के साथ काम करेंगे। अरविंद केजरीवालजी का स्वास्थ्य और शिक्षा का जो मॉडल है, उसे हमने दिल्ली और पंजाब में सफलतापूर्वक लागू किया है, उसी तरह गुजरात में भी घर-घर तक पहुंचाएंगे।

SIR मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी, किसी भी प्रकार की आपत्ति या शंका हो, तो चुनाव आयोग को स्वयं आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनाव आयोग को "72 घंटे में माफी मांगो" जैसी शर्तें नहीं रखनी चाहिए या दबावपूर्ण निर्देश नहीं देने चाहिए, बल्कि पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से पूरी प्रक्रिया की जनता के सामने संतोषजनक जांच करनी चाहिए। यदि SIR द्वारा नकली जनता बनाई जाती रही तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? यह तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। UGC मुद्दे पर उन्होंने कहा कि UGC बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों और बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करता है। मेरा स्पष्ट कहना है कि किसी भी मुद्दे पर यदि किसी को आपत्ति हो—चाहे वह शैक्षणिक संस्थाएं हों, चुनाव आयोग हो या कोई अन्य संवैधानिक संस्था—तो स्पष्टीकरण देना और संतोष प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब यदि पंजाब की बात करें तो देश के लिए सबसे अधिक बलिदान देने वाले राज्यों में पंजाब अग्रणी रहा है। जब देश को अनाज की जरूरत पड़ी, तब पंजाब के किसानों ने ग्रीन रिवोल्यूशन कर अनाज के भंडार भर दिए। फिर भी आज तक पंजाब की अपनी राजधानी नहीं है। चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, वास्तव में पंजाब का अधिकार बनता है। यह मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है। पंजाब के पास अपनी अलग हाईकोर्ट नहीं है। जबकि नॉर्थ-ईस्ट के छोटे-छोटे राज्यों के पास भी अपनी हाईकोर्ट है। इस कारण मामलों की पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है और व्यवस्था पर भारी बोझ है। आज के समय में कोई भी राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी अपनी राजधानी न हो। चंडीगढ़ पंजाब की ही राजधानी है और पंजाब की ही राजधानी होनी चाहिए।

पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस और जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरों को विस्तार किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09706/09705 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09706 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर स्पेशल को 30 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09705 जयपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 29 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09706 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 29 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मजबूत बिक्री और बेहतर परिचालन के दम पर मारुति सुजुकी की कमाई में इजाफा, तीसरी तिमाही में मुनाफा 4 प्रतिशत बढ़ा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजों से एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बदलते बाजार हालात और चुनौतियों के बावजूद कंपनी अपनी पकड़ बनाए हुए है। 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,879 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बीते वर्ष इसी तिमाही में कंपनी ने 3,727 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। मुनाफे में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है, जब ऑटो सेक्टर बढ़ती लागत, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता मांग में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। कंपनी के अनुसार, इस तिमाही में परिचालन स्तर पर उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा। यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात में भी स्थिरता देखने को मिली, जिसका सीधा असर राजस्व पर पड़ा। तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी का कुल राजस्व बढ़कर 49,904 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 38,764 करोड़ रुपये था।

"मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" यात्री जागरूकता अभियान का DRM ने किया शुभारंभ

(जीएनएस)। यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने, वैध टिकटिंग को प्रोत्साहित करने तथा रेल यात्रा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी को सशक्त करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा जनजागरूकता अभियान "मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" शुरू किया गया। इस अभियान का उद्घाटन वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा वडोदरा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में किया गया। यह अभियान 28 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। वडोदरा स्टेशन पर इस अभियान की शुरुआत करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने यात्रियों से आव्हान किया कि वे टिकट लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाएँ, और देश की प्रगति का हिस्सा बने और जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए बताया कि भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा

कर्त्तव्य है कि हम जब भी यात्रा करें, टिकट लेकर यात्रा करें, टिकट लेना गर्व की बात है, हमारी शान है। आपके इस योगदान से न सिर्फ देश का विकास होता है बल्कि रेलतंत्र भी मजबूत होता है। रेलगाड़ियाँ मॉडर्न और सुरक्षित होती है और रेल नेटवर्क के साथ साथ रेल सुविधाओं ने उन्नयन और सुधार भी होता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने मीडिया को आगे बताया कि वडोदरा मंडल पर लगभग 1.4 लाख यात्री प्रतिदिन रेल से सफ़र करते है। मंडल पर यात्रियों में डिजिटल माध्यमों से अपना अनारक्षित टिकट बुक करने में पिछले वर्ष के मुकाबले 35 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटलाइजेशन के विज़न तथा 'डिजिटल इंडिया' पहल के प्रति यात्रियों के बढ़ते विश्वास और सहभागिता को दर्शाती है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारतीय रेल का RailOne ऐप यात्रिओं के लिए सुविधाओं के बारे में ऑल इन वन मोबाइल ऐप है। इसके बारे में भी लोगों को इस अभियान के अंतर्गत जागरूक किया जाएगा। RailOne एक ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से यात्री आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन स्थिति, PNR जानकारी, भोजन सेवा तथा यात्री सहायता जैसी अनेक सेवाओं का एक ही स्थान पर लाभ उठा सकते हैं।

वडोदरा के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह अभियान 28 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। वडोदरा मंडल के अंतर्गत यह अभियान वडोदरा, आनंद, एकतानगर एवं भरुच स्टेशनों पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत स्टेशन तथा विभिन्न डिजिटल व जनसंचार माध्यमों द्वारा व्यापक जनसंपर्क गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी।

असारवा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास तेज़ी से प्रगति पर असारवा रेलवे का कायाकल्प: व्यापक आधुनिकीकरण एवं यात्री सुविधाओं का विकास

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद क्षेत्र के असारवा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत तीव्र गति से किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म तथा यात्री सुविधाओं का व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आधुनिक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। पुनर्विकास कार्यों के अंतर्गत स्टेशन भवन का नवीनीकरण, प्लेटफॉर्म शेड का निर्माण, प्लेटफॉर्म रिसर्फेसिंग तथा पार्किंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही विभिन्न कार्य प्रगति पर हैः प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लगभग 34,000 वर्गफुट तथा प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर लगभग 50,000 वर्गफुट क्षेत्रफल में कवर शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को धूप, वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा मिलेगी।

40 फीट चौड़े एवं 82 फीट लंबे फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से प्लेटफार्मों के बीच सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया को प्लेटफॉर्म संख्या 1 को प्लेटफॉर्म संख्या 2/3 से जोड़ने के लिए 40 फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की आवाजाही सुगम, सुरक्षित एवं सुचारु होगी। आधा एकड़ के करीब विशाल पार्किंग विकसित की गई है, जिसमें दोपहिया, चारपहिया एवं ऑटो रिक्शा के लिए पृथक एवं सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया गया है, जिससे यातायात प्रबंधन में सुधार होगा। इस योजना के अंतर्गत 20 फीट चौड़ा भव्य प्रवेश एवं निकास द्वार, लगभग 6500 वर्गफुट क्षेत्रफल की कैनोपी सहित डेडिकेटेड पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ जोन तथा सुव्यवस्थित सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया जा रहा है।

स्टेशन परिसर में आकर्षक लैंडस्केपिंग एवं विशाल कॉन्कोर्स क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक एवं आरामदायक वातावरण प्राप्त होगा। स्टेशन फसाड़ एवं प्रवेश द्वार का आकर्षक सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे स्टेशन को आधुनिक एवं विश्वस्तरीय पहचान प्राप्त होगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु डीलक्स ए.सी., नॉन-ए.सी. एवं सामान्य प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, आधुनिक टिकटिंग काउंटर, डिजिटल सूचना प्रणाली, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्तमान में असारवा स्टेशन पर 12 नियमित एवं 4 विशेष ट्रेनों का ठहराव है तथा प्रतिदिन लगभग 10,600 यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को प्रतिदिन लगभग 1,00,000 यात्रियों की सुविधा के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हो रहा यह पुनर्विकास न केवल यात्री सुविधाओं में गुणात्मक सुधार लाएगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन एवं रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। पुनर्विकसित असारवा रेलवे स्टेशन आधुनिक, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ अहमदाबाद क्षेत्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा और 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा 01 फ़रवरी, 2026 से और चार उपनगरीय ट्रेन सेवाओं की शुरुआत

पश्चिम रेलवे पर कुल सेवाओं की संख्या 1410 हो जाएगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुविधा बढ़ाने और उपनगरीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 01 फ़रवरी 2026 से 12-कोच वाली 04 अतिरिक्त नॉन-एसी उपनगरीय ट्रेन सेवाएँ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन अतिरिक्त सेवाओं के शुरू होने से पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय खंड पर कुल उपनगरीय सेवाओं की संख्या 1406 से बढ़कर 1410 हो जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह वृद्धि कांदिवली–बोरीवली के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद संभव हो पाई है। छठी लाइन के कमीशन होने के पश्चात बोरीवली और बांद्रा टर्मिनस के बीच सभी बांद्रा टर्मिनस की ओर आने/जाने वाली लम्बी दूरी की ट्रेनों को पाँचवीं एवं छठी लाइन पर स्थानांतरित किया गया है, जिससे परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इन 04 नई सेवाओं में से 02 अप दिशा में और 02 डाउन दिशा में होंगी, जो स्लो मोड में परिचालित की जाएंगी। अप दिशा में एक सेवा भायंदर से बांद्रा के लिए होगी, जो 11:39 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि दूसरी सेवा भायंदर से चर्चगेट के लिए होगी, जो 12:14 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, डाउन दिशा में 02 अतिरिक्त सेवाएँ बांद्रा से भायंदर के लिए होंगी, जो बांद्रा से क्रमशः 04:30 बजे और 13:21 बजे प्रस्थान करेंगी।

इन सेवाओं के शामिल होने के परिणामस्वरूप कुछ मौजूदा उपनगरीय सेवाओं के समय में मामूली परिवर्तन किए गए हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे कृपया इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर यात्रा करें।

जुल्म, खामोशी और एक खौफनाक फैसला: सूरत में पति की हत्या ने खोले रिश्तों के काले सच

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत शहर से सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को झकझोर दिया है, बल्कि समाज में छिपे घरेलू अत्याचार और वैवाहिक हिंसा के भयावह सच को भी उजागर कर दिया है। यहां 37 वर्षीय एक महिला को अपने ही पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को अंदर तक हिला देने वाले हैं। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि उस लंबे दर्द, प्रताड़ना और मजबूरी की कहानी है, जो एक महिला वर्षों तक सहती रही और अंत में एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला और उसका पति मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले थे। रोज़गार की तलाश में पति मुंबई में मजदूरी करता था और महीने में कभी-कभार सूरत आता था, जहां पत्नी रहती थी। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य दंपती का जीवन लगता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे महिला की जिंदगी एक डरावने सपने से कम नहीं थी। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका पति ताकत बढ़ाने वाली गोलियों और दवाओं का सेवन करता था और उनके असर में उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। इस दौरान वह न सिर्फ बेरहमी से पेश आता, बल्कि कई बार उसे गंभीर रूप से घायल भी कर देता था।

महिला के अनुसार, यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। पति के अत्याचार केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी उसे तोड़ चुके थे। यौन उत्पीड़न के कारण कई बार उसे गंभीर चोटें आईं, यहां तक कि रक्तस्राव जैसी स्थिति भी बन जाती थी। उसने कई बार इस यातना का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे डराया-धमकाया गया। समाज, बदनामी और अकेलेपन के डर से वह किसी से खुलकर कुछ कह नहीं पाई। धीरे-धीरे उसके भीतर गुस्सा, भय और बेबसी जमा होती गई, जिसने अंततः उसे एक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी कीमत अब वह कानून के सामने चुका रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, महिला ने पति से छुटकारा पाने के लिए पहले भी प्रयास किए थे। 1 जनवरी की रात उसने हल्दी वाले दूध में चूहे मारने की दवा मिलाकर पति को पिला दी। उस समय उसकी मंशा साफ थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और पति की जान नहीं गई। हालांकि, जहर का असर उसकी सेहत पर पड़ चुका था और वह कमजोर हो गया था। इसके कुछ दिन बाद, 5 जनवरी को जब पति की हालत पहले से ही खराब थी और वह घर पर मौजूद था, तब दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ। उसी रात, महिला ने पति को काबू में किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद महिला ने पूरे मामले को बीमारी से हुई मौत का रूप देने की कोशिश की।

पश्चिम रेलवे चलाएगी साबरमती-बीकानेर और पोरबंदर-जोधपुर के बीच वन-वे स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-बीकानेर और पोरबंदर-जोधपुर के बीच विशेष किराये पर दो वन-वे स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09491 साबरमती–बीकानेर वन-वे स्पेशल

ट्रेन संख्या 09491 साबरमती–बीकानेर वनवे स्पेशल शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को साबरमती से 17.50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06.30 बजे बीकानेर पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़, जोधपुर एवं नागौर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09291 पोरबंदर-जोधपुर वन-वे स्पेशल

ट्रेन संख्या 09291 पोरबंदर-जोधपुर स्पेशल रविवार, 01 फरवरी 2026 को पोरबंदर से 19.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.00 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में वांसजालिया, लालपुर जाम, जामनगर, हापा, राजकोट, वांकानेर, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, महेसाणा, पाटन, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल एवं समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09491 और 09291 की बुकिंग 29 जनवरी,2026 सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भारत वैश्विक ऊर्जा हब बनने की राह पर: पीएम मोदी से मुलाकात ने बढ़ाया विदेशी निवेशकों का भरोसा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 के तहत आयोजित एक राउंडटेबल में वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के 27 सीईओ और वरिष्ठ कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक में भारत में निवेश और कारोबारी विस्तार के अवसरों पर व्यापक चर्चा हुई और वैश्विक उद्योग जगत ने देश की विकास यात्रा और नीति स्थिरता पर गहरी भरोसा जताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक गति अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में देश को निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए सरकार की तैयारियों और नीतिगत ढांचे को स्पष्ट किया। मोदी ने विशेष रूप से कहा कि भारत वैश्विक ऊर्जा मांग-आपूर्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाएगा और यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर निवेश अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अन्वेषण और उत्पादन में लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर और कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) क्षेत्र में 30 अरब अमेरिकी डॉलर के अवसर मौजूद हैं।

बैठक में प्रधानमंत्री ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था, रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल एकीकरण, समुद्री ऊर्जा और शिपबिल्डिंग सहित पूरी ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश के अवसरों पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में अनिश्चितताएं जरूर हैं, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। नवाचार, सहयोग और गहरी साझेदारी के माध्यम से भारत पूरी ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार बनने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह राउंडटेबल संवाद उद्योग और सरकार के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें उद्योग से सीधे प्राप्त फीडबैक नीतिगत ढांचे को और बेहतर बनाने, क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान करने और भारत को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में स्थायी विकास और स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

इस बैठक में टोटलएनर्जीज, बीपी, विटोल, एचडी हुंडई, एचडी केएसओई, आकर, लांजाटेक, वेदांता, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम (IEF), एक्सेलेरेट, वुड मैकेंज़ी, ट्रैफिगुरा, स्टाट्सऑयली, प्राज, रिन्यू और एमओएल जैसी प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों के सीईओ एवं प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत में निवेश स्थिर और दीर्घकालिक रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से न केवल आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि रोजगार सृजन, तकनीकी उन्नति और वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बैठक विदेशी निवेशकों और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के लिए भारत में निवेश के अवसरों को समझने और नीति स्थिरता का भरोसा पाने का महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। इसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में भारत ऊर्जा निवेश के क्षेत्र में एक विश्वसनीय हब के रूप में उभर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र का विकास न केवल घरेलू मांग को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारत की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे नवाचार, सहयोग और तकनीकी क्षमता के माध्यम से भारत में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं और देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों में सहयोग करें।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार निवेशकों को नीति स्थिरता, सरल नियामक प्रक्रिया, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और सहयोगी माहौल प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह निवेश न केवल ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि लाएगा, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।

इस बैठक के बाद भारत में वैश्विक ऊर्जा निवेशकों और कंपनियों का भरोसा और बढ़ गया है और विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश और वैश्विक साझेदारी के लिए प्रमुख गंतव्य बन सकता है।